नईदुनिया

भोपाल, 2 अगस्त 2026

खास-खबरें

भारत, रवांडा द्विपक्षीय व्यापार संबंध गहरे होंगे, संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने जतायी प्रतिबद्धता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अफ्रीकी देश रवांडा ने भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिजों, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जतायी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि भारत-रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की राजधानी में शुक्रवार को सम्पन्न हुई दो दिवसीय पहली बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी निवेश और व्यापार संबंध बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जतायी। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र को सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गयी। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार ने किया जबकि रवांडा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रवांडा गणराज्य के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के एशिया, प्रशांत और मध्य पूर्व मामलों के महानिदेशक वर्जिल रवान्यागाटारे ने किया।व्यापार में विविधता लाने, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और परिवहन क्षेत्र संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक स्थायी, संरचित और आवधिक शीर्ष तंत्र की स्थापना करने का अवसर मिला है।

हुंडई, निसान, आयशर, किआ की बिक्री बढ़ी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: मजबूत ग्राहक धारणा के बीच जुलाई में हुंडई मोटर इंडिया, किया इंडिया और निसान मोटर इंडिया ने यात्री वाहनों की बिक्री के अपने नये रिकॉर्ड बनाये हैं।

हुंडई मोटर इंडिया की निर्यात समेत कुल बिक्री जुलाई में 25 प्रतिशत बढ़कर 75,360 इकाई पर पहुंच गयी जो उसका मासिक बिक्री का नया रिकॉर्ड है। कंपनी ने शनिवार को बताया कि जुलाई में घरेलू बिक्री 23 प्रतिशत और निर्यात 31 प्रतिशत बढ़ा। घरेलू बाजार में उसने 54,210 वाहन और वैश्विक बाजार में 21,150 वाहन बेचे।

कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जुलाई में उसका निर्यात 12 साल से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। क्रेटा की बिक्री 18,088 इकाई रही जो इस कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक है। आई20 की बिक्री भी 6,738 इकाई के साथ इस कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रही है।

आयशर मोटर्स लिमिटेड के ट्रकों और बसों की घरेलू बिक्री (इलेक्ट्रिक वाहनों समेत) 18 फीसदी बढ़कर 7,575 इकाई हो गयी। वहीं निर्यात में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी और यह 470 इकाई पर रही। वॉल्वो ट्रक और बसों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 196 इकाई पर पहुंच गयी। इस प्रकार कुल बिक्री 16 प्रतिशत ऊपर 8,241 इकाई दर्ज की गयी। किया इंडिया ने जुलाई में मासिक बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 28,200 वाहन बेचे। यह एक साल पहले की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।

निसान मोटर इंडिया ने भी जुलाई में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए घरेलू बाजार में 4,518 वाहन बेचे। यह सालाना आधार पर 218 प्रतिशत की वृद्धि है। उसका निर्यात 4,821 इकाई पर रहा। निर्यात समेत कुल बिक्री 9,339 इकाई दर्ज की गयी।

राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व से 1.09 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त किश्त

पूंजीगत और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र ने समय से पहले जारी की राशि

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व में उनके हिस्से के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किश्त जारी की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह राशि अगस्त माह में 10 अगस्त को जारी होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और पूंजीगत तथा विकास संबंधी व्यय में तेजी लाना है।

मंत्रालय के अनुसार यह कदम राज्यों को विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा पूंजीगत निवेश को गति देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप उठाया गया है। अगस्त 2026 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों के शुद्ध संग्रह से राज्यों को वितरित राशि में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को

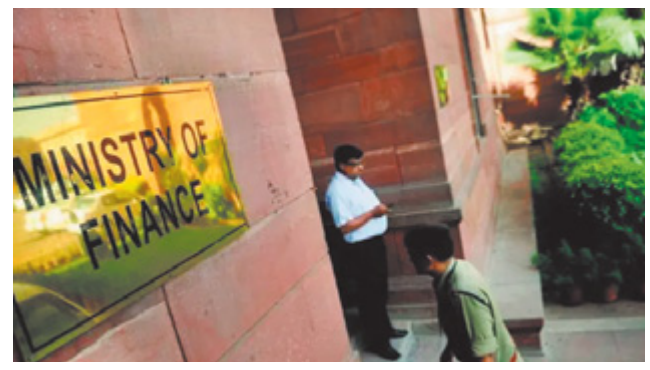

7,022 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये मिले हैं।

इसके अलावा ओडिशा को 4,819 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,504 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये, गुजरात को 4,094 करोड़ रुपये, झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये तथा असम को 3,552 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अन्य राज्यों में केरल को 2,597 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 2,370 करोड़ रुपये, पंजाब को 2,176 करोड़ रुपये, हरियाणा को 1,484 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश को 1,476 करोड़ रुपये, उत्तराखंड को 1,244 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 996 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को भी उनके निर्धारित हिस्से के अनुसार राशि जारी की गई है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस अतिरिक्त हस्तांतरण से राज्यों को विकास कार्यों और पूंजीगत निवेश की गति बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

सरकार ने कहा- दिल्ली में पेट्रोल 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकता था, ई-20 से इंजन पर प्रतिकूल असर का कोई प्रमाण नहीं

एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के दौरान यदि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं की गई होती तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 125 रुपये प्रति लीटर हो सकती थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुक्रवार को एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की लागत, खाद्य सुरक्षा और सब्सिडी से जुड़े विभिन्न दावों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के कारण उपभोक्ताओं को पेट्रोल पर प्रति लीटर लगभग 30 रुपये तक की राहत मिली। मंत्रालय के अनुसार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद देश में उपभोक्ताओं को पूर्व निर्धारित कीमतों पर खरीदे गए घरेलू एथेनॉल की मदद से राहत मिली। हर एक लीटर पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल की हिस्सेदारी होने के कारण खुदरा कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव का पूरा असर नहीं पड़ा। वर्तमान में दिल्ली में मानक ई-20 पेट्रोल (91 ऑक्टेन) की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि

100 ऑक्टेन पेट्रोल 169 रुपये प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 75 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा गया था। इसके बाद मई में पेट्रोल और डीजल के दामों में 7.5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई। खाद्यान्न के उपयोग को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल कार्यक्रम के लिए भारतीय खाद्य निगम के सब्सिडी वाले चावल या गरीबों के लिए निर्धारित अनाज का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए ऐसे किसी भी खाद्यान्न का डायवर्जन नहीं किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के संयुक्त अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि ई-10 ईंधन के लिए डिजाइन की गई बीएस-3, बीएस-4 और बीएस-6 श्रेणी की गाड़ियों को ई-20 ईंधन पर चलाने से उनकी क्षमता और आयु के आधार पर ईंधन दक्षता में 2 से 6 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इससे पहले राज्यसभा में सरकार ने यह कमी लगभग 3 से 5 प्रतिशत बताई थी।

सरकार के अनुसार एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम को वैज्ञानिक परीक्षण और चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। ई-20 ईंधन पर जाने का निर्णय फ्यूल सिस्टम, इंजन की मजबूती, ड्राइवेबिलिटी, मटेरियल कम्पैटिबिलिटी और एमिशन परफॉर्मेंस की विस्तृत जांच के बाद लिया गया।

इस प्रक्रिया में वाहन निर्माताओं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों तथा चीनी और अनाज उद्योग से भी लगातार परामर्श किया गया। सरकार का कहना है कि देश में 20 करोड़ से अधिक टू-व्हीलर और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रही हैं तथा एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण इंजन खराब होने का कोई प्रमाणित या सत्यापित मामला सामने नहीं आया है।

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल

अंतिम दो दिनों में करीब 82 लाख करदाताओं ने भरे रिटर्न, विभाग ने जताया आभार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो गई। आयकर विभाग के अनुसार तय समय सीमा तक देशभर में 5.9 करोड़ करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। विभाग ने समय पर रिटर्न दाखिल करने वाले सभी करदाताओं का आभार व्यक्त किया है।

आयकर विभाग के अनुसार अंतिम दो दिनों में रिटर्न दाखिल करने की रफ्तार काफी तेज रही। 30 जुलाई को लगभग 42 लाख करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किए, जबकि 31 जुलाई को करीब 40 लाख लोगों ने आयकर रिटर्न जमा किया। इस तरह केवल अंतिम दो दिनों में लगभग 82 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।

इस वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नौकरीपेशा करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर छूट का लाभ मिलने के बाद पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसके साथ ही इस बार सभी करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पहला आकलन वर्ष है, जिसमें बड़ी संख्या में करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किए।

आयकर विभाग का कहना है कि अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में रिटर्न दाखिल होने के बावजूद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित की गई। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए सहयोग मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।

पिछले आकलन वर्ष 2025-26 में कुल 9.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। विभाग के अनुसार चालू आकलन वर्ष के लिए 31 जुलाई तक प्राप्त रिटर्न की संख्या निर्धारित समय सीमा तक दाखिल किए गए रिटर्न को दर्शाती है। आगे संशोधित रिटर्न और अन्य निर्धारित प्रावधानों के तहत दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।

टाटा की यात्रा वाहनों की घरेलू बिक्री 58 फीसदी बढ़ी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की दूसरी सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की घरेलू बिक्री जुलाई में 58 प्रतिशत बढ़कर 62,611 प्रतिशत पर पहुंच गयी। कंपनी ने शनिवार को बताया कि उसने जुलाई में 1,149 यात्री वाहनों की निर्यात किया। इस प्रकार यात्री वाहनों की उसकी कुल बिक्री 63,760 इकाई रही। कंपनी ने जुलाई में घरेलू और वैश्विक बाजार में कुल 15,217 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। यह पिछले साल जुलाई की तुलना में 114 प्रतिशत अधिक है। वाणिज्यक वाहन बनाने वाली टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री जुलाई में 28 फीसदी की वृद्धि के साथ 33,876 इकाई पर पहुंच गयी। कंपनी का निर्यात 128 प्रतिशत बढ़कर 5,765 करोड़ रुपये रहा।

जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये के पार

सालाना आधार पर 15.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अप्रैल से जुलाई तक भी संग्रह में दोहरे अंक की वृद्धि

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में जुलाई 2026 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह पिछले वर्ष जुलाई 2025 के 1.83 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15.4 प्रतिशत अधिक है। जून 2026 में जीएसटी संग्रह 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा था। सरकार के अनुसार जुलाई के आंकड़े अस्थायी हैं और अंतिम आंकड़े जारी होने पर इनमें मामूली बदलाव संभव है।

जुलाई के दौरान केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपये तथा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 1.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह हुआ।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों, अप्रैल से जुलाई तक, कुल जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत बढ़कर 8.4 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान

अवधि में यह 7.6 लाख करोड़ रुपये था। इसी अवधि में घरेलू जीएसटी संग्रह 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7.21 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 6.61 लाख करोड़ रुपये था।

राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो महाराष्ट्र जुलाई में 32,210 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ पहले स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। गुजरात में 19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12,923 करोड़ रुपये, कर्नाटक में 12 प्रतिशत बढ़कर 13,854 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9,651 करोड़ रुपये तथा तेलंगाना में 19 प्रतिशत वृद्धि के साथ 5,819 करोड़ रुपये का संग्रह दर्ज किया गया।

वहीं कुछ राज्यों में जीएसटी संग्रह में गिरावट भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में संग्रह 10 प्रतिशत घटा। तमिलनाडु में एक प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में पांच प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सिक्किम में सबसे अधिक 59 प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि हिमाचल प्रदेश में 22 प्रतिशत और उत्तराखंड में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

जीएसटी संग्रह को अर्थव्यवस्था की स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। अधिक संग्रह से उत्पादन, उपभोग और कर अनुपालन में सुधार का संकेत मिलता है। देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई 2017 से लागू है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया गया था।

वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता दिल्ली में 192 रुपये की कटौती

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने का असर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम यथावत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: तेल विपणन कंपनियों ने एक अगस्त से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर अब 2,930 रुपये के बजाय 2,738 रुपये में उपलब्ध होगा। इस प्रकार राजधानी में इसकी कीमत में 192 रुपये की कमी की गई है। वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 942 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में आई गिरावट का लाभ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिया गया है। इससे पहले जुलाई में भी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए गए थे। उस समय दिल्ली में कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई थी।

विभिन्न महानगरों में कीमतों में कमी का स्तर अलग-अलग रहा है। कोलकाता में 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर अब 2,872.50 रुपये का मिलेगा, जहां इसकी कीमत में 209 रुपये की कमी की गई है। मुंबई में सिलेंडर 194 रुपये सस्ता होकर 2,691.50 रुपये का हो गया है, जबकि चेन्नई में 200 रुपये की कटौती के बाद इसकी नई कीमत 2,906 रुपये निर्धारित की गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये पर स्थिर रखी गई है।

तेल विपणन कंपनियों के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव के कारण मार्च से जून के बीच एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सीमित बदलाव किया गया। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी आने के बाद वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार दूसरे महीने घटाए गए हैं।

महिंद्रा की यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री जुलाई में 20 प्रतिशत बढ़ी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाहनों की घरेलू बिक्री जुलाई में 20 प्रतिशत बढ़कर 60,048 इकाई पर पहुंच गयी।

कंपनी ने शनिवार को बताया कि जुलाई में वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 25,204 इकाई पर रही। तिपहिया की बिक्री भी 53 फीसदी बढ़ी और 14,538 इकाई दर्ज की गयी।

वाणिज्यिक वाहनों और तिपहिया की घरेलू बिक्री तथा निर्यात मिलाकर उसकी कुल बिक्री 1,03,860 इकाई पर रही। यह पिछले साल जुलाई की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी के ट्रैक्टरों की बिक्री एक साल पहले की तुलना में 21 प्रतिशत बढ़कर 32,643 इकाई पर पहुंच गयी। कंपनी ने जुलाई में 1,777 ट्रैक्टरों का निर्यात किया जो सालाना तीन प्रतिशत वृद्धि है।

दोपहिया बिक्री में जुलाई में जारी रही मजबूती

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री जुलाई में भी मजबूत रही और हीरो मोटोकॉर्प तथा रॉयल इनफील्ड की बिक्री क्रमश: 19 प्रतिशत तथा 34 प्रतिशत बढ़ गयी।

जापानी कंपनी होंडा मोटर की भारतीय इकाई होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की बिक्री सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 5.42 लाख इकाई पर पहुंच गयी। कंपनी ने शनिवार को बताया कि जुलाई उसने घरेलू बाजार में 4.76 लाख वाहन बेचे जो एक साल पहले के मुकाबले दो प्रतिशत अधिक है। वहीं, उसका निर्यात 35 प्रतिशत बढ़कर 66 हजार इकाई पर रहा।

हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की घरेलू बिक्री जुलाई में 19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,78,689 इकाई पर पहुंच गयी। कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की इकाई 'वीडा' की बिक्री 22,714 इकाई रही। इलेक्ट्रिक वाहन समेत कुल घरेलू बिक्री 5,01,403 इकाई रही। यह 22 प्रतिशत की सालाना वृद्धि है।

कंपनी ने बताया कि उसने 32,013 वाहनों की निर्यात भी किया जो सालाना आधार पर 14.31 प्रतिशत कम है। इस प्रकार कुल बिक्री 5,33,416 इकाई पर पहुंच गयी। यह आंकड़ा पिछले साल जुलाई के मुकाबले 19 प्रतिशत अधिक है। आयशर मोटर्स की मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड की कुल बिक्री 34 फीसदी बढ़कर 1,18,232 इकाई पर पहुंच गयी। इसमें घरेलू बिक्री 38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,05,317 इकाई रही। कंपनी ने जुलाई में 12,915 मोटरसाइकिलों का निर्यात किया। यह एक साल पहले के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है।

महँगाई बढ़ती लागत के बीच कई प्रमुख कंपनियां कीमतों में करेंगी वृद्धि, महंगाई पर बढ़ सकता है दबाव

फेस्टिव सीजन से पहले रोजमर्रा के सामान महँगे होने की आशंका

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई/नई दिल्ली: फेस्टिव सीजन से पहले देश की प्रमुख एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं। टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, डिशवॉशिंग बार, पेंट, टायर और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम आगामी तिमाही में बढ़ सकते हैं। कंपनियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे माल और ऊर्जा की लागत बढ़ी है, जिससे उत्पादन खर्च में लगातार इजाफा हो रहा है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने संकेत दिए हैं कि वह होम केयर श्रेणी के उत्पादों, विशेष रूप से डिटर्जेंट और डिशवॉशिंग बार की कीमतों में वृद्धि करेगी। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी निरंजन गुप्ता ने बताया कि कच्चे तेल से जुड़े डेरिवेटिव्स की लागत बढ़ने के कारण होम केयर उत्पादों की कीमतों में सोच-समझकर बढ़ोतरी की जा रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा डोडला डेयरी, एशियन पेंट्स तथा अन्य कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं।

ऊर्जा लागत में लगातार वृद्धि का असर अन्य कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है। हैवेल्स इंडिया अपने उत्पादों के दाम करीब आठ प्रतिशत तक बढ़ा चुकी है, जबकि

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने टाटा साल्ट की कीमतों में लगभग सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। कंपनियों का मानना है कि बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो गई है।कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हो रही है, जब अगस्त से नवंबर तक चलने वाला फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। इस अवधि में उपभोक्ताओं की खरीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है और कई कंपनियों की वार्षिक बिक्री का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी दौरान आता है। मजबूत मांग के कारण कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर स्थानांतरित करने की स्थिति में हैं।

जून में खाद्य और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर पहुंच गई। हालांकि यह अभी भी दो से छह प्रतिशत के सहनीय दायरे में बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 5.1 प्रतिशत रह सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट और कंपनियों के मार्जिन पर बढ़ते दबाव के कारण कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य हो गई है। कंपनियों के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग अभी स्थिर बनी हुई है। वहीं, कमजोर मानसून और अल नीनो की आशंका आने वाले महीनों में महंगाई के दबाव को और बढ़ा सकती है। 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में भी ब्याज दरों को स्थिर रखने की संभावना जताई जा रही है।